

लोक सभा
अतारांकित प्रश्नसंख्या 2294
3 अगस्त 2015 को उत्तर के लिए

नए इस्पात संयंत्र

†2294. श्री नन्दी एल्लैया:
श्री अजय निषाद:
डॉ. कभमपति हरिबाबू:
श्री अजय मिश्रा टेनी:
श्री गुत्था सुकेंद्र रेड्डी:
श्रीमती रीती पाठक:
श्री जैदेव गल्ला:
श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में वर्तमान में निर्माणाधीन नए इस्पात संयंत्रों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या क्या है;
- (ख) क्या उक्त संयंत्रों के पूरा करने में लागत और समय में बढ़ोतरी हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके संयंत्र-वार कारण क्या हैं;
- (ग) क्या सरकार का आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड और उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में और अधिक नए इस्पात संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;
- (घ) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) इन संयंत्रों को समयबद्ध ढंग से चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात और खान राज्य मंत्री

(श्री विष्णुस देव साय)

(क) और (ख) : इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है तथा सरकार की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में सीमित है। नए इस्पात संयंत्रों के निर्माण से संबंधित निर्णय अनिवार्य रूप से संबंधित कंपनियों द्वारा उनके वाणिज्यिक सोच-विचारों के आधार पर लिए जाते हैं।

एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा नागरनार , छत्तीसगढ़ में एक नए एकीकृत इस्पात संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना को दिसम्बर 2016 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है , जबकि इसे पूरा करने का मूल समय कार्यक्रम मई, 2015 था। फिर भी, लागत वृद्धि की कोई प्रत्याशा नहीं है। परियोजना का क्रियान्वयन मुख्य रूप से महत्वपूर्ण कार्यों का ठेका देने, वन स्वीकृति की प्राप्ति और इंजीनियरी एवं फेब्रिकेटेड सामग्री की आपूर्ति इत्यादि में विलम्ब होने तथा ठेका एजेंसियों द्वारा अपर्याप्त संसाधन जुटाए जाने के कारण प्रभावित हुआ है।

(ग) से (ङ) : इस्पात मंत्रालय अपने अधीन पीएसयू और राज्य के पीएसयू के बीच संयुक्त उद्यम में स्पेशल परपज व्हीगकल (एसपीवी) की स्थापना करके ग्रीन फील्ड इस्पात परियोजनाओं का विकास किए जाने को सुगम बना रहा है। स्टील एसपीवी की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ में एमओयू पर दिनांक 09.05.2015 को और झारखंड में दिनांक 28.06.2015 को हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि इस्पात एसपीवी और खनन एसपीवी बनाने के लिए परियोजना संबंधी विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके।
